

प्रेषक,

डी०पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग—१

देहरादून: दिनांक: १० अप्रैल, 2013

विषय— अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड को देय फीस में संशोधन।

महोदय,

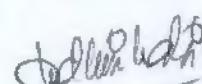
उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-०८ / XXXVI(1) / (एक) 2008-43-एक (1) / 2003 दिनांक 07.01.2008 को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल हेतु आवङ्द अपर महाधिवक्ता को दिनांक 01.01.2013 से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— रिटेनर फीस नियत	₹ 15,000/- (₹ पन्द्रह हजार मात्र) प्रति माह
2— मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष ₹ 10,000/- (₹ पैरवी/बहस करने की फीस (चाहे एक से अधिक दस हजार मात्र) कितने मामलों में बहस की जाये) प्रति कार्यदिवस	
2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं०-०४ के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-००-आयोजनेत्तर-११४-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-०३-महाधिवक्ता-००-१६ व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।	
3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-०५ NP/XXVII(5)/13-14 दिनांक 05.04.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।	

भवदीय,

(डी०पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव

कमशः-२



संख्या- 1264/XXXVI(1)/2013-43 एक(1)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
- 3— महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 5— समस्त अपर महाधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 6— वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 7— वित्त अनुभाग—५, उत्तराखण्ड शासन ।
- 8— गार्ड फाईल / एन०आई०सी० ।

आज्ञा से

Dharmendra Singh

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)

संयुक्त सचिव